भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3751 का उत्तर

दक्षिण रेल जोन में रेल परियोजनाएं

3751. श्री अ. मनि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान दक्षिण रेल जोन में शुरू की गई प्रमुख रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या दक्षिण रेल जोन में अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए विशेष रूप से निधि जारी की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो विद्युतीकरण, स्टेशनों के उन्नयन और सिग्नल प्रणाली सहित आधुनिकीकरण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(छ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त रेलवे सहित सभी रेल जोनों को आवंटित विकास निधि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): रेल परियोजनाएं लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों,

केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड तथा धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल वार ब्यौरा जिसमें लागत, व्यय और परिव्यय शामिल है, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएँ (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 44,488 किलोमीटर तथा लागत 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना निर्माण/अनुमोदन/निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	मार्च, 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	01.04.2024 तक शेष लंबाई (कि.मी.)
नई लाइन	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, (12 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण) सहित दक्षिण रेलवे ज़ोन में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 27 रेल परियोजनाएं जिनकी कुल लंबाई 2,436 किलोमीटर है, 36,710 करोड़ रुपए की लागत पर योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 655 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 7,758 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	12	1018	24	1526
आमान परिवर्तन	3	748	604	3267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	12	670	27	2965
कुल	27	2436	655	7758

<u>तमिलनाडु</u>

दक्षिण रेलवे जोन का अधिकांश भाग तमिलनाडु और केरल राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	6,362 करोड़ रु. (7 गुना से अधिक)

यद्यपि निधि आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, किंतु परियोजना के निष्पादन की गति त्वरित भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे, राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करती है और रेल परियोजनाओं का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति इस प्रकार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	3389 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	866 हेक्टेयर (26%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार ने परियोजनाओं को निष्पादित करने की गति बढ़ा दी है, परंतु इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण लंबित कुछ मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना के नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1	टिंडीवनम-तिरुवनमलाई नई लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2	अट्टीपट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3	मोराप्पुर-धर्मापुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4	मन्नारगुडी-पट्टूकोट्टाई (41 कि.मी.)	152	0	152
5	तंजावूर- पट्टूकोट्टाई (52 कि.मी.)	196	0	196

केरल

दक्षिण रेलवे ज़ोन का अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु और केरल राज्य में पड़ता है। केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रु./वर्ष
2024-25	3,011 करोड़ रु. (8 गुना से अधिक)

केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार हैः

केरल में परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत कुल भूमि	475 हेक्टेयर
अधिगृहीत भूमि	64 हेक्टेयर (13%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	411 हेक्टेयर (87%)

भारत सरकार परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तैयार है, बहरहाल इनका पूरा होना केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करता है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सरकार को 2111.83 करोड़ रु. जमा कराए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए

केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	परियोजना के नाम	कुल आवश्यक भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण के लिए शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	अगंमाली-सबरीमाला नई लाइन (111 कि.मी.)	416	24.4	391.6
2.	एर्णाकुलम - कुम्बलम कहीं-कहीं दोहरीकरण (8 कि.मी.)	4.2	1.59	2.61
3.	कुम्बलम - तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 कि.मी.)	10.3	5.30	5
4.	त्रिवेंद्रम - कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 कि.मी.)	40.15	32.69	7.46
5.	षोरणूर - वल्लतोल दोहरीकरण (10 कि.मी.)	4.77	0	4.77

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दक्षिण रेलवे ज़ोन में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 932 करोड़ रुपए की लागत की कुल 75 किलोमीटर लंबाई वाली कुल 04 परियोजनाओं (01 नई लाइन और 03 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

बहरहाल, पिछले पांच वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दक्षिण रेलवे ज़ोन में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 2802 किलोमीटर लंबाई की कुल 30 परियोजनाओं (06 नई लाइन और 24 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत वहन परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत के हिस्से को जमा कराने, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, किसी परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

दक्षिण रेलवे की कुल 5,040 मार्ग किलोमीटर की बड़ी लाइनों में से 4,801 मार्ग किलोमीटर को पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है और शेष 239 मार्ग किलोमीटर के खंडों का विद्युतीकरण शुरू किया जा चुका है।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान, दक्षिण रेलवे को सिगनल और दूरसंचार कार्यों के लिए 1822.51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 30.11.2024 तक 1598.75 करोड़ रुपए उपयोग किए जा चुके हैं।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,

एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 116 स्टेशन दक्षिण रेलवे में पड़ते हैं। दक्षिण रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

क्षेत्रीय रेलवे	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
दक्षिण रेलवे	116	अलाप्पुझा, अंबासमुद्रम, अंबत्तूर, अंगडीप्पुरम, कलाडी के लिए अंगमाली, अराक्कोणम जंक्शन, अरियालुर, अवदी, बोम्मिडी, चलाकुडी, चंगनाचेरी, चेंगलपट्टू जंक्शन, चेंगन्नूर स्टेशन, चेन्नई बीच, चेन्नई एग्मोर, चेन्नई पार्क, चिदंबरम, चिन्ना सेलम, कोयम्बटूर जंक्शन, कोयम्बटूर नॉर्थ, कुन्नूर, डिंडीगुल, डॉ. एमजी रामचंद्रन सेंट्रल, एर्णाकुलम, एर्णाकुलम टाउन, इरोड, एट्टुमानूर, फेरोक, गुडुवनचेरी, गुइंडी, गुम्मिडीपूंडी, गुरुवयूर, जोलारपेट्टई जंक्शन, कन्याकुमारी टर्मिनस, कन्नूर, कराईकल, कराईकुडी जं., करूर जं., कासरगोड, काटापाडी जं., कयानकुलम, कोल्लम जं. (क्विलोन), कोविलपट्टी, कोझिकोड मेन (कालीकट), कुलितुरई,

		कुंभकोणम, कुट्टीपुरम, लालगुडी, मदुरै, माम्बलम, मनापरई, माहे, माम्बलम, मानापराई, मैंगलोर सेंट्रल, मैंगलोर जं., मन्नारगुडी, मवेलीकारा, मयिलादुथुराई जं., मेट्टुपलयम, मोरप्पुर, नागरकोइल जंक्शन, नमक्कल, नेय्यातिनकारा, नीलांबुर रोड, ओट्टापलम, पलानी, परमाकुडी, परप्पनंगडी, पेराम्बुर, पोदनूर जं., पोलाची, पोलुर, पुडुचेरी, पुदुक्कोट्टई, पुनालुर, राजापलायम, रामनाथपुरम, रामेश्वरम, सेलम, सामलपट्टी, शोलावंदन, षोर्णानूर जं., श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुथुर, सेंट थॉमस माउंट, सुल्लुरपेट्टा, ताम्बरम, तेनकासी, थलास्सेरी, तंजावुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुवरुर, त्रिशूर, तिरुचेंदूर, तिरुनेलवेली जं., तिरुप्पादिरिप्पुलियूर, तिरुपत्तूर, तिरुपुर, तिरुसुलम, तिरुत्तानी, तिरुवल्ला, तिरुवल्लुर, तिरुवन्नामलाई, थिरुपनिथुरा, तूतीकोरिन, उदगमंडलम, वडकारा, वर्कला, वेल्लोर कैंट, विल्लुपुरम जं., विरुधुनगर, वृद्धाचलम जं, वडकांचेरी

दक्षिण रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चिह्नित 116 स्टेशनों में से 107 स्टेशनों के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजनाओं का कार्य निष्पादन तेजी से हो रहा है। उदाहरण के लिए:-

मदुरै स्टेशन पर, पूर्वी छोर पर मल्टी-लेवल टू-व्हीलर पार्किंग और विद्युत सबस्टेशन के संरचना संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं और टर्मिनल भवन के पूर्वी छोर, दोनों ओर मल्टी-लेवल कार पार्किंग, एयर कॉनकोर्स, पार्सल ऊपरी पैदल पुल, सबवे आदि से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

चेन्नै एग्मोर स्टेशन पर, पार्सल भवन का संरचना संबंधी कार्य पूरा कर दिया गया है और दोनों ओर मल्टी-लेवल कार पार्किंग, जीआई रोड साइड टर्मिनल भवन आदि से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

सामलपट्टि स्टेशन पर, नए मुख्य टर्मिनल भवन और मुख्य प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है और द्वितीय प्रवेश द्वार के पार्किंग क्षेत्र, प्लेटफॉर्म के सतह की ऊंचाई बढ़ाने, परिसर की दीवार का निर्माण आदि का कार्य शुरू कर दिया गया है।

कोल्लम स्टेशन पर सर्विस बिल्डिंग का कार्य पूरा हो चुका है। मल्टी-लेवल कार पार्किंग, टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिणी छोर (ब्लॉक-ए और बी) और पार्सल बिल्डिंग का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिणी छोर (ब्लॉक-सी), एयर कॉनकोर्स, ऊपरी पैदल पुल, प्लेटफॉर्म में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टर आदि का कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

कुट्टिपुरम स्टेशन पर, परिचलन क्षेत्र के कार्यों में सुधार, पार्किंग क्षेत्र, प्रतीक्षालय, नए प्लेटफार्म शेल्टर, नए पोर्च और प्रवेश रैंप के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है तथा बुकिंग कार्यालय के सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है।

थालास्सेरी स्टेशन पर, कॉनकोर्स क्षेत्र, बुकिंग कार्यालय, पार्किंग क्षेत्र में सुधार, नए प्लेटफार्म शेल्टर, पोर्च और कवर्ड वॉकवे के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है तथा परिचलन क्षेत्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त होती है और विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों जैसे दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि की आवश्यकता होती है। यह विकास कार्य ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने

वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होता है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भारतीय रेल में स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते समय सुविधाओं का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास के लिए निचली कोटि के स्टेशन की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। पिछले तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान, दक्षिण रेलवे के लिए योजना शीर्ष-53 के तहत 2,595 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और पिछले तीन वित्त वर्षों और चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान 1,635 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

*****